RNI NO. PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

पेज 07

मलाइका अरोड़ा का बोल्ड अवतार देख फैंस हुए मदहोश

VOL: 03 | ISSUE 174 | FRIDAY DATE 17-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

'सोनम वांगचुक का जीवन बचाने के लिए सभी चिकित्सीय प्रयास हों', हाईकोर्ट ने दिया डॉक्टरों से रोजाना निगरानी का आदेश

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई**

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 18 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और मेडिकल स्थिति के संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों से जांच कराई जाए और उनके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी सभी चिकित्सीय प्रयास किए जाएं। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। लगातार बिगड़े स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत से सोनम वांगचुक का जीवन बचाने के लिए सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, 'उनका रोज स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जब भी वह सरकारी डॉक्टरों को जांच की अनुमति देते हैं, तब उनकी जांच की जाती है। कई बार निजी डॉक्टर भी आकर उनका परीक्षण करते हैं।' इस पर अदालत ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से उनकी जांच करें। जीवन अमूल्य है।' इसके बाद हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए। अदालत ने कहा, 'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निदेर्शों के आधार पर बताया है कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन सरकारी डॉक्टरों की ओर से नियमित निगरानी की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 34.29 लाख रुपये का सोना जब्त, बुर्के में छिपाकर लाई थी महिला यात्री

अहमदाबाद, 16 जुलाई । शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने सोने की तस्करी के एक और प्रयास को विफल कर दिया। अबूधाबी से अहमदाबाद पहुंची एक महिला यात्री के पास से करीब 34.29 लाख रुपये मूल्य का 233 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद कर जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फ्लाइट संख्या 3एल111 से अबूधाबी से अहमदाबाद पहुंची महिला यात्री की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कस्टम्स अधिकारियों ने उसका पैसेंजर प्रोफाइलिंग के तहत चयन किया। इसके बाद महिला को रोककर उसकी गहन जांच और पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान पता चला कि महिला ने कस्टम्स ड्यूटी की चोरी करने के इरादे से अपने बुर्के के अंदर बेहद चालाकी से 24 कैरेट सोने के दो टीटी बार (गोल्ड बिस्किट) छिपा रखे थे। दोनों बिस्किटों का कुल वजन 233 ग्राम पाया गया।

नौवीं में तीसरी भाषा बच्चों पर बढ़ाती है दबावः सुप्रीम कोर्ट की सलाह

दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी कर कहा है कि नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा को अनिवार्य नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बच्चों पर बढ़ते शैक्षिक दबाव और तनाव को देखकर महत्वपूर्ण सलाह दी है। यह टिप्पणी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तीन भाषा नीति के खिलाफ चल रहे विवाद के बीच आई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी.

सीबीआई की कार्रवाई : रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए केएपीएल के एमडी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के प्रबंध निदेशक अनुराग दानायक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 15 जुलाई को नोएडा में उन्हें 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस कार्रवाई की जानकारी एजेंसी ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी। सीबीआई के अनुसार, अनुराग दानायक ने भोपाल स्थित एक फर्म, जो केएपीएल की अधिकृत सर्विस एजेंट है और मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों को दवाइयों की आपूर्ति करती है, से करीब 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह रिश्वत फर्म के सर्विस एजेंट एग्रीमेंट को मंजूरी देने, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लंबित नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और फर्म को अतिरिक्त सरकारी संस्थान आवंटित करने के बदले मांगी गई थी। इसके अलावा चालू वर्ष में दवाइयों की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन में भी हिस्सा मांगा गया था।

उत्तराखंड के छात्र पेपरलीक के विरुद्ध 'छात्रों की गूंज' से जुड़े : राहुल

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह 17 जुलाई को देहरादून में होंगे क्योंकि उत्तराखंड को पेपर लीक का 'केन्द्रबिंदु' बना दिया गया है। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में ऐसा तंत्र विकसित हो गया है, जहां पटवारी, लेखपाल और अन्य पद योग्यता से नहीं बल्कि अपराधियों द्वारा तय किए गए दामों पर मिलते हैं। कांग्रेस नेता ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश में कहा कि सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया इसके बावजूद पेपर लीक होते रहे। कानून केवल कागजों तक सीमित रहा और प्रश्नपत्र बाजार में बिकते रहे। उन्होंने कहा कि वर्षों मेहनत करने वाले युवाओं का हक छीन लिया गया है और किसी दूसरे ने पैसे देकर उनकी नौकरी खरीद ली। यह केवल पेपर लीक नहीं, बल्कि युवाओं के रोजगार और भविष्य की चोरी है। श्री गांधी ने उत्तराखंड के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों से इस लड़ाई में शामिल होने का आ'ान करते हुए कहा कि वह उनके साथ खड़े हैं।

'विकसित उड़ान' से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी कनेक्टिविटी: नायडू

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में शुरू की गयी 'विकसित उड़ान' योजना में पिछली योजना की तुलना में कई बदलाव किये गये हैं और इससे देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यहां विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के लिए आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि 10 साल पहले शुरू की गयी 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना काफी सफल रही। अपनी तरह की उस पहली योजना से सीखते हुए नयी 'विकसित उड़ान' योजना में बदलाव किये गये हैं।

राष्ट्र प्रथम' की भावना से युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहा है शहीद भगत सिंह कॉलेज : रेखा गुप्ता

डीयू में 16 अगस्त से 'अटल कैंटीन', जल्द मिलेंगे 50 नए यू-स्पेशल बस मार्ग

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शहीद भगत सिंह कॉलेज को स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह महाविद्यालय पिछले छह दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का विकास कर रहा है। श्रीमती गुप्ता आज यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

इस अवसर पर उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज को स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह महाविद्यालय पिछले छह दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का विकास कर रहा है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी युवा शक्ति और शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है।

शहीद भगत सिंह कॉलेज जैसे संस्थान देश के भविष्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण पद्धतियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं। दिल्ली सरकार भी इसी दृष्टिकोण के अनुरूप राजधानी के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में 16 अगस्त को 'अटल कैंटीन' का उद्घाटन किया जायेगा।

दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी, सरकार करेगी 400 करोड़ रुपये का निवेश

रेखा गुप्ता ने कहा, अब नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे दिल्ली के युवा

दिल्ली सरकार ने राजधानी को देश का अग्रणी उद्यमिता और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेशन नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम निवेश किया जाएगा, जिससे युवाओं के बेहतरीन बिजनेस आइडियाज को जमीन पर उतारा जा सके। इस नीति के तहत दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना कर छात्रों को आर्थिक मदद, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा।

जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसका भविष्य भी मजबूत होगा : राजनाथ सिंह

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में, यह विश्वास बनाना है, कि देश का कोई भी कोना अब दूर नहीं है। यह बात गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि हम यह समझते हैं, कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे मजबूत होगा। इसलिए हम आगे भी, भविष्य में इसी प्रकार, कार्य करते रहेंगे। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) तकनीकी संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, हवाई मार्ग और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ-साथ हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, हम सीमावर्ती गाँवों को, जिन्हें कभी अंतिम गाँव

कहा जाता था, उन्हें हम देश के प्रथम गाँव के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है, कि देश का कोई भी नागरिक मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस न करे। और बीआरओ ने इस निश्चय को पूरा करने में, बड़ी भूमिका निभाई है।

यहां राजनाथ सिंह ने कहा, 'हमारा प्रयास हो कि हम ऐसा भारत बनाएँ, जहाँ सीमाएँ केवल सुरक्षित ही न हों, बल्कि सबसे जुड़ी हुई भी हों।

दिल्ली में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम, एलजी संधू ने खुद लगाई झाड़ू

'छींरा पहनरा' की पवित्र रस्म के साथ दिल्ली में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

राजधानी में भी महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा की भव्य शुरूआत हो चुकी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को हौज खास विलेज रोड स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से 48वीं श्री जगन्नाथ रथयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संत-महात्मा, धर्मगुरु और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रथयात्रा की शुरूआत से पहले दिल्ली के एलजी सरदार टीएस संधू ने सदियों पुरानी और पवित्र 'छींरा पहनरा' की रस्म को व्यक्तिगत रूप से निभाया। इस रस्म के तहत उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों के आगे खुद झाड़ू लगाई। इस परंपरा के महत्व पर बात करते हुए एलजी ने कहा, 'यह रस्म हमें याद

दिलाती है कि समाज में कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, वो भगवान की सेवा और भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। यह सदियों पुरानी परंपरा हमें विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का गहरा संदेश देती है।'

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

घर से दवा लेने निकली किशोरी लापता

साहिबाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई । लिंकरोड थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी (17) नौ जुलाई को घर से दवा लेने गई और सदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अब परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित मां ने बताया कि नौ जुलाई की सुबह करीब 9:30 बेटी घर से दवा लेने गई थी। कई घंटे बीतने पर भी वह घर नहीं लौटीं। इसके बाद खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देर रात करीब 11 बजे एक अंजान नंबर से कॉल आई, लेकिन पिक करने से पहले ही कट गई। उसकी लोकेशन मऊ जिले में आई है। परिजनों ने क्षेत्र निवासी युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। प्रभारी एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। सर्विलांस टीम भी जांच में जुटी हुई है।

बिजली कटौती पर ऊर्जा निगम कार्यालय पहुंचे 150 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

लोनी, यूटर्न/ 16 जुलाई । बिजली कटौती से परेशान लोग ऊर्जा निगम कार्यालय पर पहुंचे 150 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। उन पर अधिकारियों से अभद्रता करने और ऊर्जा निगम कार्यालय की लाइन क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। अवर अभियंता ने लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। अवर अभियंता सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 जुलाई को डीएलएफ विद्युत उपकेंद्र पर 150 से अधिक लोगों ने लाइट न आने पर प्रदर्शन किया था। कुछ शरारती तत्वों ने उपकेंद्र में तैनात कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। लोगों ने उपकेंद्र में चलती मशीनों के साथ छेड़छाड़ की। लोगों ने विद्युत कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर चालू फीडर बंद करवा कर ताला लगा दिया। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई और करीब छह घंटे तक करीब 26 हजार उपभोक्ता प्रभावित हुए। फीडर बंद होने से उपकेंद्र ओवरलोड हो गया और दस एमवीए के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की नौबत आ गई। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर आशीष झा, ओम प्रकाश पांडे, गोविंद शर्मा, विजय कुमार, अशोक कुमार, अमरजीत, धर्मवीर व प्रदीप समेत 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

स्कूल से लौट रही दो छात्रों पर मकान का छज्जा गिरा, चोटिल

लोनी, यूटर्न/ 16 जुलाई । बॉर्डर थानाक्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में एक जर्जर मकान का छज्जा गिर जाने से स्कूल से लौट रही दो छात्राएं चोटिल हो गईं। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। गिरते हुए छज्जे की चपेट में आने से पैर में चोट लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के बाद दोनों को छुट्टी मिल गई। इस दौरान घर के नीचे खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। शिव विहार कॉलोनी निवासी रवि ने बताया कि उनके भाई अरुण का मकान है और वह परिवार के साथ दिल्ली करावल नगर में रहते हैं। मकान काफी दिन से बंद है और देखरेख के अभाव में बुधवार दोपहर करीब 1:45 बजे मकान का छज्जा भरभराकर नीचे खड़ी कार पर गिर गया। इससे दिल्ली मंडोली स्थित राजकीय कन्या बाल विद्यालय की कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा नीतू और सोनम निवासी राहुल गार्डन कॉलोनी मलबे की ईंट लगने से चोटिल हो गई। शोर सुनकर आस पास के लोग पुलिस को मामले की जानकारी देकर चोटिल छात्राओं को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे।

हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बनने पर राजेश ठकराल का बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा में भव्य स्वागत

» **हरियाणा, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त होने पर राजेश ठकराल का बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा,नजदीक पुरानी सब्जी मंडी में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेश ठकराल ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेश के व्यापारियों की उन्नति, समाज की खुशहाली एवं जनकल्याण के लिए अरदास की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एवं संगत की ओर से राजेश ठकराल का सिरोपा एवं सम्मान स्वरूप अभिनंदन किया गया। संगत ने उन्हें चेयरमैन बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश के व्यापारियों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा होगी तथा व्यापारिक समुदाय के कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित होंगे।

इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में राजेश ठकराल के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, दीर्घायु एवं सफल कार्यकाल के लिए विशेष अरदास की गई।

उपस्थित संगत ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें प्रदेश के व्यापारियों की सेवा करने की शक्ति एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

इस अवसर पर सुभाष चुघ, राम प्रकाश परुथी , रविंद्र खुराना, राकेश भाटिया, कृष्ण एलाहवादी , मुनीष कालड़ा ,कुलदीप जोगी, सतीश कालड़ा, सौरभ कथूरिया, संदीप नागपाल, कुलदीप ठकराल , प्रवीण सिंगला,

कुलदीप सैनी, मोनू ठकराल , मोहन लाल चूचड़ा, रामू बजाज, नरेंद्र नारंग, रिंकू टुटेजा एवं अजय मेहता सहित बड़ी संख्या में संगत एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

'न पी सकते हैं, न नहा सकते हैं' ...

दिल्ली के हरिनगर के लोगों का दूषित पानी को लेकर फूटा गुस्सा

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

राजधानी दिल्ली के हरिनगर इलाके के आशा पार्क, फतेह नगर और आसपास की कॉलोनियों के निवासियों ने पिछले दो महीनों से दूषित और सीवर मिला पानी मिलने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से लगातार बदबूदार, पीले और काले रंग का पानी आ रहा है, जिससे पीने, नहाने, खाना बनाने और अन्य घरेलू काम करना मुश्किल हो गया है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तत्काल समाधान की मांग की है।

स्थानीय निवासी मंजीत सिंह ने बताया कि आशा पार्क और फतेह नगर दोनों क्षेत्रों में नलों से सीवर मिला पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी से इतनी तेज बदबू आती है कि उसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है। उनके मुताबिक, सड़कों पर भी कई जगह पानी भर गया है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं।

मंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार स्थानीय विधायक श्याम शर्मा से

शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि लोग पीने के लिए दूसरे इलाकों से बोतलों में पानी लाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि गंदे पानी के कारण वे कई दिनों से ठीक से नहा भी नहीं पाए हैं। एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बच्चों और बुजुर्गों की सेहत की है।

उन्होंने कहा कि गंदा पानी घरों की टंकियों में भर जाता है, जिसके बाद लोगों को बार-बार टंकियां साफ करानी पड़ रही हैं। पहले जहां टंकी की सफाई का खर्च कम था, वहीं अब सफाई करने वाले 1,500 से 3,000 रुपये तक मांग रहे हैं। इसके बावजूद अगले ही दिन फिर वही गंदा पानी टंकी में भर जाता है।

एक अन्य निवासी पवन सिंह ने कहा कि पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि सीवर की बदबू पूरे इलाके में फैली हुई है और लोग अपने रिश्तेदारों को भी घर बुलाने से बच रहे हैं।

खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, परिसीमन विधेयक के संशोधन पर सर्वदलीय बैठक की मांग

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किए जाने से पहले सरकार के परिसीमन संबंधी संशोधित विधेयकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। अपने पत्र में खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने इस साल की शुरूआत में इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की मांग बार-बार की थी। उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर सरकार के परिसीमन प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक का अनुरोध किया था, लेकिन उन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। खड़गे ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के हश्र का भी जिक्र किया, जो 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में संवैधानिक रूप से अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा।

ग्रेटर नोएडा के तिलपता में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा

निमार्णाधीन दो मंजिला मकान और दुकान गिरे

» **ग्रेटर नोएडा, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित तिलपता गांव में गुरुवार को नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। साकीपुर रोड पर चल रही नाले की खुदाई के दौरान पास में स्थित एक निमार्णाधीन दो मंजिला मकान और दुकान अचानक भरभराकर जमीन पर गिर गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। हादसे की चपेट में बिजली के पोल और विद्युत तार भी आ गए, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना के समय मकान और दुकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तिलपता में सड़क और नाला निर्माण का कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा है। गुरुवार को जेसीबी मशीन से नाले की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान निमार्णाधीन दुकान और मकान के सामने से बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई गई, जिससे भवन की नींव कमजोर हो गई। कुछ ही देर बाद निमार्णाधीन ढांचा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मानसून से पहले नाला निर्माण का कार्य जल्दबाजी में किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

लोगों का आरोप है कि खुदाई के दौरान आसपास के भवनों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण की लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस के अनुसार थाना सूरजपुर क्षेत्र के साकीपुर रोड तिलपता निवासी ओमवीर पुत्र रमेश की निमार्णाधीन दुकान अचानक गिर गई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के तहत जेसीबी से दुकान के सामने की मिट्टी हटाई गई थी। संबंधित दुकान की नींव नाले की ओर बनी हुई थी, जिसके कारण मिट्टी हटते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरी दुकान ढह गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।

मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और बिजली विभाग की टीम क्षतिग्रस्त पोल एवं तारों की मरम्मत में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्य के कारण औषधालय के कुछ काउंटर बंद , मरीज परेशान

फरीदाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई । जिला नागरिक अस्पताल में औषधालय के सामने चल रहे मरम्मत एवं निर्माण कार्य से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल में लंबे समय से चल रहे मरम्मत व निर्माण कार्य के चलते औषधालय के कुछ काउंटरों को बंद कर दिया गया है। इससे मरीजों को सीमित काउंटरों पर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को हो रही है, जिन्हें दवा लेने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। सेक्टर-7 निवासी रामनिवास (68) ने बताया कि घुटनों के दर्द के कारण चलना-फिरना मुश्किल है। निर्माण कार्य के कारण उन्हें दवा काउंटर तक पहुंचने में परेशानी हुई और करीब आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। वहीं एसजीएम नगर निवासी सुभद्रा देवी (72) ने बताया कि डॉक्टर से जांच कराने के बाद दवा लेने पहुंचीं तो केवल कुछ काउंटर ही खुले मिले। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास गोयल ने बताया कि अस्पताल में मरम्मत एवं निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दवा काउंटर पर बुजुर्ग व गर्भवतीयों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि परेशानी को देखते हुए कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही सभी काउंटर सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे।

अखिल भारतीय किसान सभा ने मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को सौंपा, ज्ञापन

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 16 जुलाई । संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आ'ान पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों और खेती को बर्बाद करने वाली अमेरिका के साथ कृषि डील के विरोध में हरियाणा के राज्यसभा सांसद संजय भाटिया पानीपत के आवास पर किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए लिखित मांग पत्र के माध्यम से मांग कि की 20 जुलाई 2026 से संसद के मानसून सत्र में कृषि डील रद्द करने की किसानों की मांग को संसद में उठाएं। आवास पर राज्यसभा सांसद संजय भाटिया की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी श्रीमती अंजू भाटिया ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया मैं सांसद महोदय के सामने आपकी मांग को रखूंगी।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, जिला सचिव राजपाल, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला सह संयोजक सुनील दत्त, जिला कोषाध्यक्ष कुंवर सिंह छोकर, जिला उप प्रधान दिलावर सिंह राठी, सह सचिव सीताराम शर्मा, प्रेस सचिव फौजी रोहतास आर्य, रामकिशन कुंडू, राम रूप सैनी, राजवीर गिरी, गुलाब सिंह, शीशपाल शर्मा, एस ए खान, राहमेहर , अमित कुमार, जयपाल कादयान, कृष्ण देशवाल, राजेंद्र छोकर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन राज्य के महासचिव आदि ने किया।

अखिल भारतीय किसान सभा ने पानीपत जिले के किसने की बिजली संबंधित मांगों को लेकर बिजली विभाग के एस. ई जिला कार्यालय पानीपत पर विरोध प्रदर्शन कर तुरंत समाधान की मांग की।

बरवाला में बनेगा 50 बेड का नया सिविल अस्पताल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का जताया आभार

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/ 16 जुलाई । क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में बरवाला में 50 बेड क्षमता वाले नए सिविल अस्पताल भवन के निर्माण को मंजूरी मिली है। भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह धीरू ने बताया कि नए अस्पताल भवन के बनने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा मरीजों को इलाज के लिए अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्षेत्र वासियों की बहुत लंबे समय से यह डिमांड थी कि बरवाला शहर में एक बड़ा तथा सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल बने। क्योंकि बरवाला के आसपास बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार एवं का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि नए अस्पताल भवन के निर्माण से बरवाला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होकर समय पर पूरा होगा, जिससे आमजन को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पानीपत रिफाइनरी ने चलाया व्यापक जन-जागरूकता, अभियान

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 16 जुलाई । स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स (पीआरपीसी) द्वारा 1 से 15 जुलाई तक स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता एवं सामुदायिक गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के माध्यम से स्वच्छता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा समाज में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख श्री एम. एल. डहरिया द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पखवाड़े के दौरान पीआरपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) टीम द्वारा आसपास के गांवों के 8 सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विद्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए डस्टबिन भी वितरित किए गए। अभियान के अंतर्गत लगभग 600 सफाई कर्मियों एवं मिड-डे मील कर्मियों को स्वच्छता किट वितरित की गई। यह पहल समाज में स्वच्छता बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करने का प्रतीक रही। इसके अतिरिक्त, पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने तथा स्वच्छ भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का संदेश देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया।

पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत आसपास के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन भी कर रहा है। यह सेवा ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता (पर्सनल हाइजीन), स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। इस प्रकार, पीआरपीसी का यह प्रयास इस संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाता है कि स्वच्छता की शुरूआत स्वयं से होती है, और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है।

स्वच्छता पखवाड़ाझ2026 के अंतर्गत आयोजित इन गतिविधियों ने आसपास के गांवों एवं समुदायों में स्वच्छता के महत्व को प्रभावी रूप से रेखांकित किया तथा लोगों को स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। पानीपत रिफाइनरी का यह प्रयास सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है तथा स्वच्छ, स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे

ग्रेटर नोएडा, यूटर्न/ 16 जुलाई । गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत कासना थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1 किलो 350 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई को थाना कासना पुलिस क्षेत्र में नियमित चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान कस्बा कासना क्षेत्र से पुलिस ने चांद पुत्र रफीक को गिरफ्तार किया।

तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के गांजे की अवैध बिक्री से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मु.अ.सं. 138/2026 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चांद पुत्र रफीक, निवासी गली नंबर-3, मेट्रो पिलर नंबर-99 के सामने, सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष बताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में भी सेक्टर-39 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है।

चैनत की जीत जनएकता, लोकतांत्रिक संघर्ष और जनता के विश्वास की जीत है : बृजलाल बहबलपुरिया

» हरियाणा, यूटर्न/ 16 जुलाई ।

जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) हिसार के अध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया ने गांव चैनत की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा गांव के लिए 4 इंच का पेयजल कनेक्शन स्वीकृत किया जाना ग्रामीणों के शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संगठित संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल चैनत गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के उन किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तथा आसपास के गांवों के लोगों की भी है जिन्होंने हर परिस्थिति में आंदोलन का मजबूती से साथ दिया।

बृजलाल बहबलपुरिया ने कहा कि इस जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत गांव की एकजुटता रही। विशेष रूप से महिलाओं ने जिस साहस, धैर्य और समर्पण के साथ आंदोलन में भागीदारी निभाई, उसने पूरे संघर्ष को नई ऊर्जा प्रदान की। किसान भाइयों ने भी गांव की इस न्यायपूर्ण लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर हर कदम पर सहयोग दिया। उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन देने वाले सभी सामाजिक संगठनों, खाप प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने जनता की इस जायज मांग के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जनता के अधिकारों, किसानों और ग्रामीणों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। चैनत गांव के आंदोलन में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकताओं ने लगातार ग्रामीणों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया। कांग्रेस का विश्वास है कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं का समाधान संवाद, संवेदनशीलता और जनहित की भावना से होना चाहिए, न कि लोगों को लंबे समय तक आंदोलन करने के लिए मजबूर करके।

बृजलाल बहबलपुरिया ने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने समय रहते ग्रामीणों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया होता तो लोगों को लंबे समय तक धरना देने, किसानों को परेशानियां झेलने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार तब जागी जब जनता ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं पर कुंभकरण की नींद से जागने के बजाय समय रहते निर्णय लेने चाहिए, ताकि विकास कार्य संघर्ष का विषय न बनें।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, कंपनी संचालक समेत तीन गिरफ्तार, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

» नोएडा, यूटर्न/ 16 जुलाई ।

नोएडा के सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का पदार्फाश किया है, जो देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों और उद्यमियों को ऑनलाइन मार्केटिंग, खरीदार उपलब्ध कराने तथा फर्जी सर्टिफिकेट देने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बना रहा था।

पुलिस ने इस गिरोह का संचालन करने वाले कंपनी संचालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीपीयू, सिम कार्ड और धोखाधड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई को थाना सेक्टर-63 में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान इस संगठित साइबर ठगी गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि सेक्टर-63 स्थित ए-135 भवन में फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। यहां से देशभर के व्यापारियों और उद्योगपतियों को फोन कर ऑनलाइन मार्केटिंग सेवाएं, नए खरीदार उपलब्ध कराने और विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र जारी कराने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। आरोपियों द्वारा फर्जी दस्तावेज और प्रमाणपत्र तैयार कर लोगों का विश्वास जीतने के बाद आर्थिक ठगी की जाती थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंपनी संचालक रणबीर सिंह, उसके सहयोगी ललित कुमार तथा ज्योति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रणबीर सिंह गाजियाबाद के इंदिरापुरम का निवासी है, जबकि ललित कुमार नोएडा के बरौला क्षेत्र का रहने वाला है। महिला आरोपी ज्योति भी रणबीर सिंह की पत्नी है और कॉल सेंटर के संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 39 स्मार्ट मोबाइल फोन, 9 कीपैड मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप, 36 सीपीयू, 32 सिम कार्ड तथा विभिन्न टैक्स इनवॉइस, फर्जी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बरामद किए हैं।

प्रोफेसर की नहीं, परीक्षार्थी की तलाश

संदीप शर्मा

बिहार में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए जारी नए ड्राफ्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे यहां शिक्षा नीति अक्सर विश्वविद्यालयों में नहीं, सचिवालयों की फाइलों में तैयार होती है। परिणाम यह हुआ कि जिस मसौदे को सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता का दस्तावेज बता रही है, उसे पीएचडी शोधार्थी अपने वर्षों के परिश्रम का अवमूल्यन मान रहे हैं। विरोध इतना तीखा है कि विश्वविद्यालयों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है—क्या बिहार शोध संस्कृति को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा संस्कृति को विश्वविद्यालयों पर थोपना चाहता है? यह विवाद केवल नियुक्ति नियमों का नहीं है। यह उस सोच का संघर्ष है जिसमें एक ओर वर्षों का शोध, प्रयोग, पुस्तकालयों की धूल और अकादमिक साधना है, तो दूसरी ओर कुछ घंटों की लिखित परीक्षा को योग्यता का अंतिम पैमाना बनाने का आग्रह। सरकार का तर्क सीधा है। वह कहती है कि लिखित परीक्षा से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और भाई-भतीजावाद तथा साक्षात्कार आधारित मनमानी समाप्त होगी। यह तर्क पूरी तरह निराधार नहीं है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्तियों पर वर्षों से पक्षपात, जातीय समीकरण, राजनीतिक प्रभाव और साक्षात्कार की अपारदर्शिता के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए चयन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता से शायद ही कोई असहमत होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पारदर्शिता का अर्थ केवल लिखित परीक्षा है? यदि कोई विद्यार्थी सात वर्ष तक शोध करता है, यूजीसी-नेट और जेआरएफ जैसी कठिन परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित करता है, सेमिनारों में भाग लेता है और विषय पर नई समझ विकसित करता है, तो क्या उसकी पूरी अकादमिक यात्रा का मूल्यांकन तीन घंटे की परीक्षा से किया जा सकता है? विश्वविद्यालय और कर्मचारी चयन आयोग में मूलभूत अंतर होता है। विश्वविद्यालय केवल नौकरी देने वाली संस्था नहीं है; वह ज्ञान निर्माण का केंद्र है। वहां शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी में प्रश्न पूछने की क्षमता, आलोचनात्मक दृष्टि और शोध की संस्कृति विकसित करता है। यदि शिक्षक चयन की कसौटी केवल प्रतियोगी परीक्षा बन जाएगी तो विश्वविद्यालय धीरे-धीरे कोचिंग संस्थानों की शाखा में बदलने का खतरा पैदा होगा। विडंबना यह है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगातार शोध, नवाचार और बहुविषयक शिक्षा पर बल देती है। केंद्र सरकार शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की बात करती है। दूसरी ओर यदि राज्यों में पीएचडी की उपयोगिता ही कम होती दिखाई दे तो यह राष्ट्रीय लक्ष्य के विपरीत संकेत होगा। बिहार का दुर्भाग्य यह भी रहा है कि वर्षों तक विश्वविद्यालयों में नियमित नियुक्तियां नहीं हुईं। हजारों पद रिक्त पड़े रहे। अनेक शोधार्थी अपनी युवावस्था का सबसे उत्पादक समय नियुक्ति की प्रतीक्षा में बिताते रहे। किसी ने तीस वर्ष की उम्र में पीएचडी शुरू की तो चालीस की उम्र तक भी उसे नियमित नौकरी नहीं मिली। ऐसे में यदि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भर्ती नियम ही बदल जाएं तो असंतोष स्वाभाविक है। यह केवल रोजगार का संकट नहीं, बल्कि नीति की विश्वसनीयता का संकट भी है। इस पूरे विवाद में एक और प्रश्न उठता है। यदि पीएचडी की उपयोगिता घटेगी तो आने वाले वर्षों में शोध कौन करेगा? आज भी अधिकांश विद्यार्थी शोध इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर मिलेगा। यदि अंततः चयन का मुख्य आधार केवल लिखित परीक्षा रह जाए तो युवा सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। शोध प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय खाली होने लगेंगे। ज्ञान उत्पादन की जगह नोट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संस्कृति विकसित होगी। यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि केवल पीएचडी होने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ शिक्षक बन जाता है। भारत में शोध की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं। फर्जी शोध पत्रिकाएं, नकल, कॉपी-पेस्ट शोध प्रबंध और औपचारिक शोध संस्कृति जैसी समस्याएं वास्तविक हैं। इसलिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेकिन गुणवत्ता सुधारने का उपाय शोध को महत्वहीन बना देना नहीं हो सकता। विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों पर दृष्टि डालें तो वहां सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति किसी एक परीक्षा से नहीं होती। उम्मीदवार के शोध, प्रकाशन, अध्यापन अनुभव, शोध प्रस्ताव, प्रस्तुतीकरण और विषय की गहराई का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। कई विश्वविद्यालय डेमो लेक्चर कराते हैं ताकि यह देखा जा सके कि उम्मीदवार पढ़ा भी सकता है या नहीं। आखिर विश्वविद्यालय का शिक्षक केवल परीक्षार्थी नहीं, शिक्षक और शोधकर्ता दोनों होता है। बिहार यदि वास्तव में उच्च शिक्षा में नई पहचान बनाना चाहता है तो उसे भी इसी संतुलित मॉडल की ओर बढ़ना होगा। लिखित परीक्षा हो, लेकिन उसके साथ शोध, शिक्षण अनुभव, पीएचडी, नेट, शोध प्रकाशन और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व मिले। केवल एक कसौटी से उत्कृष्ट शिक्षक नहीं चुने जा सकते। सरकार के सामने यह भी चुनौती है कि वह पारदर्शिता और अकादमिक उत्कृष्टता के बीच संतुलन बनाए। यदि पूरी प्रक्रिया केवल साक्षात्कार आधारित होगी तो पक्षपात का आरोप लगेगा। यदि पूरी प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा आधारित होगी तो विश्वविद्यालय की प्रकृति बदल जाएगी। समाधान दोनों के बीच संतुलित व्यवस्था में है। इस विवाद ने बिहार की उच्च शिक्षा की एक बड़ी विडंबना भी उजागर की है। एक ओर सरकार नए कॉलेज खोलने, विश्वविद्यालयों का विस्तार करने और हजारों नियुक्तियों की घोषणा करती है। दूसरी ओर शिक्षक चयन की प्रक्रिया ही विवादों में घिर जाती है। भवन बनाना आसान है, लेकिन विश्वविद्यालय का बौद्धिक वातावरण बनाना कठिन है। उसके लिए उत्कृष्ट शिक्षक चाहिए और उत्कृष्ट शिक्षक केवल परीक्षा से नहीं चुने जाते।

15 रुपये लीटर पेट्रोल का जुमला? इथेनॉल नीति पर जवाबदेही का समय

आज नीति का मूल्यांकन केवल पर्यावरणीय या कृषि लाभ से नहीं, बल्कि उपभोक्ता अनुभव से भी होगा। यदि जनता को अधिक कीमत भी चुकानी पड़े, माइलेज में कमी का अनुभव भी हो और भविष्य में रखरखाव की अतिरिक्त चिंता भी उठानी पड़े, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार उन शुरूआती दावों और वर्तमान परिणामों के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण दे।

भूपेन्द्र गुप्ता

देश को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अपनाने के लिए प्रेरित करते समय जनता के सामने एक आकर्षक भविष्य की तस्वीर रखी गई थी। यह कहा गया कि इथेनॉल आधारित ईंधन व्यवस्था आने पर पेट्रोल की कीमतें 15 रुपये प्रति लीटर तक आ सकती हैं। वर्षों बाद वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता आज भी ऊंची कीमत पर पेट्रोल खरीद रहा है और अब उसे यह भी बताया जा रहा है कि ए20 ईंधन के कारण कुछ वाहनों में माइलेज 3झ5 प्रतिशत तक घट सकता है। स्वयं पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना है कि कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है।

यह सर्वविदित है इथेनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू (ऊर्जा क्षमता) पेट्रोल से लगभग 30झ35 प्रतिशत कम है, तो समान मात्रा में ईंधन से मिलने वाली ऊर्जा भी कम होगी। आधुनिक ए20-अनुकूल इंजन इस अंतर की कुछ भरपाई कर सकते हैं, लेकिन भौतिकी का यह सिद्धांत नहीं बदलता कि इथेनॉल में प्रति लीटर ऊर्जा कम होती है। इसलिए माइलेज पर कुछ प्रभाव पड़ना तकनीकी रूप से अस्वाभाविक नहीं है। हाल के दिनों में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि इथेनॉल की कम कैलोरिफिक वैल्यू के कारण माइलेज पर सीमित असर पड़ सकता है, हालांकि उन्होंने वाहन क्षति के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया। सरकार का दूसरा तर्क है कि ए20 को व्यापक परीक्षण के बाद लागू किया गया और आधुनिक वाहनों में इससे सामान्य रूप से इंजन क्षति का कोई प्रमाणित पैटर्न नहीं मिला। उद्योग संगठनों और सरकार का कहना है कि ए20 के लिए परीक्षण किए गए हैं तथा वारंटी भी लागू रहेगी। फिर भी उपभोक्ता के सामने कुछ वैध प्रश्न बने रहते हैं। यदि इथेनॉल मिश्रण से तेल आयात कम होता है, तो उसका आर्थिक लाभ पेट्रोल की खुदरा कीमत में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि लाखों पुराने वाहन मूल रूप से ए20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, तो उनके लिए अलग संक्रमण योजना क्यों नहीं बनाई गई? यदि पेट्रोल पंपों और वाहन निमार्ताओं द्वारा ईंधन प्रणाली की देखभाल संबंधी अतिरिक्त सावधानियां बताई जाती हैं, तो क्या उपभोक्ता को पहले से व्यापक और स्पष्ट जानकारी दी गई?

आज नीति का मूल्यांकन केवल पर्यावरणीय या कृषि लाभ से नहीं, बल्कि उपभोक्ता अनुभव से भी होगा। यदि जनता को अधिक कीमत भी चुकानी पड़े, माइलेज में कमी का अनुभव भी हो और भविष्य में रखरखाव की अतिरिक्त चिंता भी उठानी पड़े, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार उन शुरूआती दावों और वर्तमान परिणामों के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण दे।

सरकार यह भी बताये कि ईथेनाल निर्माण में खर्च होने वाले अतिशय पानी के कारण भविष्य में पानी के संभावित संकट पर उसकी क्या नीति है?जल संकट से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी? भारत को वैकल्पिक ईंधनों की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए नए बाजार भी। लेकिन किसी भी ऊर्जा परिवर्तन की सफलता का आधार केवल नीति नहीं, बल्कि पारदर्शिता, वैज्ञानिक संवाद और उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही है। इथेनॉल नीति पर एक और प्रश्न पारदर्शिता का है। आश्चर्य यह है कि इस विषय पर सबसे अधिक सार्वजनिक पक्षधरता अक्सर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करते दिखाई देते हैं, जबकि यह नीति मूलतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है। यदि किसी मंत्री या उनके परिवार का जैव-ईंधन क्षेत्र से कोई व्यावसायिक संबंध सार्वजनिक रूप से मौजूद है, तो सरकार को स्वयं आगे बढ़कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि नीति-निर्माण, निर्णय प्रक्रिया और निजी व्यावसायिक हितों के बीच किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है। लोकतंत्र में केवल निष्पक्षता ही नहीं, बल्कि निष्पक्षता का दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है।

सरकार को अब तीन स्पष्ट कदम उठाने चाहिए—पहला, इथेनॉल नीति का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट सार्वजनिक किया जाए; दूसरा, पुराने और नए वाहनों पर वास्तविक प्रभाव का विस्तृत डेटा जारी किया जाए; और तीसरा, यह बताया जाए कि जिन आर्थिक लाभों का वादा किया गया था, वे आम उपभोक्ता तक कब और कैसे पहुंचेंगे। ऊर्जा परिवर्तन तभी सफल माना जाएगा जब उसके लाभ किसानों, पर्यावरण और उपभोक्ता—तीनों तक समान रूप से पहुंचें।

राम मंदिर दान लूट : कुतर्कों की इंतेहा ?

निर्मल रानी

प्रभु श्री राम मंदिर,अयोध्या में दान व चढ़ावे के पैसों व बहुमूल्य वस्तुओं की कथित लूट जैसे शर्मनाक कृत्य की चौतरफा निंदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चंदा व चढ़ावा चोरी मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुये केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अब तक हुई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय बताते हुये कहा है कि दानपात्र से हुई चोरी ने पूरे हिंदू समाज और राम भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है जिससे संघ परिवार भी पूरी तरह आहत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि इस महापाप में शामिल हर एक दोषी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और चंदे की पवित्रता से कोई समझौता नहीं हो सकता। संघ ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि आस्था का मामला है।

परन्तु सुप्रीम कोर्ट व संघ की चिंताओं से इतर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बेहद अफसोसनाक मामले पर भी राजनीति का ऐसा लेप चढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे विषय की गंभीरता को कम किया जा सके और भक्तों का ध्यान दूसरी तरफ भटकया जा सके। उदाहरणार्थ राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सनातन धर्म, राम भक्तों की आस्था और अयोध्या की छवि को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि विपक्ष एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की आस्था, अयोध्या की विरासत और प्रभु राम के नाम पर हमला करने का जैसे ठेका ले रखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, वे आज मंदिर के चंदे के नाम पर मचल रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, वे आज राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं ?मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे ट्रस्ट या अयोध्या को कटघरे में खड़ा करना गलत है।

उधर स्वयं को हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाला गाजियाबाद का एक व्यक्ति जिसने एक सार्वजनिक लंगर के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति हाथों से प्रसाद की थाली यह कहकर छीन ली थी कि यह लंगर मुल्लाओं के लिये नहीं। इसी व्यक्ति ने अब राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी के मामले पर बेहद विवादित और अजीबोगरीब बयान दिया है। उस ने इस मामले में आरोपियों का एक तरह से बचाव करते हुए कहा कि मंदिर हमारा है, चंदा हमारा है और अगर हमारे ही लोगों अर्थात हिंदुओं ने पैसा ले भी लिया है, तो विपक्ष या दूसरों को इससे क्या परेशानी है? दूसरों को क्यों मिर्ची लग रही है? इस ने तर्क दिया कि राम मंदिर में चंदा या दान देने वाले लोग भी भगवान राम में अटूट विश्वास रखते हैं और जिन लोगों ने यह पैसा निकाला है, वे भी भगवान राम के ही भक्त हैं। उसने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही दान का कुछ पैसा उन आरोपियों के घरों तक पहुँचा है, इसलिए इस पर किसी को भी सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, हिंदुओं का पैसा तो हिंदुओं के पास ही रहा? उस ने उल्टे विरोधियों से ही सवाल पूछा कि तुमने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है? उसके अनुसार जिन्होंने मंदिर में एक रुपया भी दान नहीं दिया, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने या सवाल उठाने का कोई हक नहीं है।

सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पर की कटौती

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। वहीं, पेट्रोल पर कटौती की है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आना था। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़कर 15.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 8.5 रुपए प्रति लीटर था। एटीएफ पर निर्यात शुल्क 7.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 14.5 रुपए प्रति लीटर हो गया।

इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को 4 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है, जिसके जवाब में ईरान ने इलाके में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए। इस महीने की शुरूआत में, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था। इसके तहत पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया, जबकि डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क में कटौती की गई। इस दौरान पेट्रोल निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (एसएईडी) को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। साथ ही, डीजल पर निर्यात शुल्क को 14 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क को 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि शुल्क को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में होने वाले बदलावों के हिसाब से समायोजित किया जा सके।

संक्षिप्त खबरें

रुपया छह पैसे टूटकर 96.31 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई, यूटर्न/ 16 जुलाई । रुपया गुरुवार को शुरूआती कारोबार में छह पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.31 पर आ गया। पश्चिम एशिया संकट के कम होने के कोई संकेत नहीं मिलने के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी की निकासी से स्थानीय मुद्रा पर दबाव बना रहा। हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक शुरूआत से रुपये को कुछ समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.28 प्रति डॉलर पर खुला। फिर फिसलकर 96.31 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट दशार्ता है। स्थानीय मुद्रा बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नौ पैसे कमजोर होकर 96.25 पर बंद हुई थी। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 100.49 पर रहा।

विंडफॉल टैक्स में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के मद्देनजर भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कमी कर थोड़ी राहत दी गई है। नई दरें 16 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, डीजल पर निर्यात शुल्क 8.5 रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 7.5 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी का जून में निराशजनक प्रदर्शन

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । कार निमार्ता स्वदेशी कंपनी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक पेशकश एक्सयूवी400 ईवी के लिए जून 2026 का महीना खासा निराशाजनक रहा। इस मॉडल की केवल 31 इकाइयां बिकीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (जून 2025 में 231 इकाइयां) की तुलना में लगभग 87 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दशार्ती है। महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी अपने आधुनिक और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती है, जिसमें बंद ग्रिल, महिंद्रा का तांबे जैसी आभा वाला प्रतीक चिन्ह और आकर्षक एलईडी हेडलैंप इसे अलग पहचान देते हैं। वाहन के भीतर प्रीमियम अनुभव देने वाला केबिन मिलता है, जिसमें 10.25 इंच का स्पर्श आधारित सूचना एवं मनोरंजन तंत्र, पूर्णतः डिजिटल चालक सूचना पटल, बिना तार के एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा, तथा दो हिस्सों वाला स्वचालित तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ईवी दो बैटरी विकल्पों (34.5 किलोवाट-घंटा और 39.4 किलोवाट-घंटा) के साथ आती है, जो क्रमशः 375 किलोमीटर और 456 किलोमीटर तक की प्रमाणित रेंज देती है। प्रदर्शन की बात करें तो यह मात्र 8.3 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और तेज चार्जिंग से लगभग 50 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। सुरक्षा के मोर्चे पर, इसमें छह एयरबैग, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और ढलान पर वाहन को पीछे लुढ़कने से रोकने वाली सुविधा जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल हैं। भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 15.49 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये के बीच है।

मानसून की स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो खाद्य तेल और दालें होंगी महंगी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई । खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों की बुआई में आई कमी का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। धान, दालों और तिलहन की कम बुआई के कारण आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आम उपभोक्ता की रसोई पर महंगाई की मार का असर पड़ेगा। जून में चावल की महंगाई दर बढ़कर 1.72 फीसदी पहुंच गई, जबकि मई में यह 0.23 फीसदी थी। इसके पीछे धान की बुआई में आई गिरावट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। 10 जुलाई तक धान का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.63 फीसदी कम दर्ज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दालों की स्थिति भी चिंताजनक है। तूअर (अरहर), उड़द और मूंग की बुआई में क्रमशः 30.29 फीसदी, 29.71 फीसदी और 10.62 फीसदी की कमी आई। इसका असर जून के महंगाई आंकड़ों में भी देखने को मिला। तूअर दाल की महंगाई दर -1.77 फीसदी से बढ़कर 0.85 फीसदी, उड़द 0.89 फीसदी से 2.16 फीसदी और मूंग 1.15 फीसदी से बढ़कर 1.71 फीसदी हो गई। इससे आने वाले समय में दालों की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड का मसौदा जारी किया

आम जनता से मांगे सुझाव

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को पक्षकारों से परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड (सीएएफई-ककक) का मसौदा जारी किया। ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित एम1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मसौदा मानदंड एम1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होंगे। एम1 श्रेणी में ऐसे यात्री वाहन शामिल हैं, जिनमें चालक के अलावा अधिकतम आठ लोगों के बैठने की क्षमता होती है। इसमें निजी उपयोग के लिए बेची जाने वाली सभी हैचबैक, सेडान और एसयूवी शामिल हैं। इस श्रेणी में वाणिज्यिक मालवाहक वाहन और बसें शामिल नहीं हैं।

मौजूदा सीएएफई-कक्क(कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) मानदंडों की अवधि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद सीएएफई-कक्क नियम लागू हो सकते हैं। सीएएफई-कक्कके तहत अनुपालन का आकलन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण तीन वर्षों का होगा, जबकि दूसरा चरण शेष दो वर्षों का होगा। प्रत्येक वर्ष के साथ ईंधन दक्षता के लक्ष्य और अधिक कड़े होते जाएंगे।

बिजली मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की निगरानी में तैयार किए गए सीएएफई-कक्कका उद्देश्य वित्त वर्ष 2032 तक वाहन बेड़े के औसत उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से घटाकर काफी कम करना है। नए ढांचे के तहत, कंप्लायंस क्रेडिट की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्रेडिट तय की गई है, जो हर वर्ष 500 रुपए बढ़ेगी। अनुपालन अवधि समाप्त होने के बाद इस्तेमाल न किए गए क्रेडिट स्वतः समाप्त हो जाएंगे और जो वाहन निमार्ता तय मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन पर जुमार्ना लगाया जा सकता है, हालांकि जुमार्ने की विस्तृत राशि का अभी उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं, सालाना 1,000 से कम वाहन बेचने वाले निमार्ताओं को इन नियमों से छूट मिलेगी।

मसौदे के पहले के संस्करणों पर उद्योग जगत की राय अलग-अलग रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इस प्रस्ताव को संतुलित बताया है, जबकि कुछ वाहन निमार्ताओं ने छोटी पेट्रोल कारों के लिए राहत की मांग की है और कुछ ने इस श्रेणी के लिए अलग नियम बनाए जाने का विरोध किया है।

अगस्त में लांच हो सकती है नई किया साइरोस ईवी

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेगमेंट में कंपनी किया इंडिया अगस्त महीने में अपनी नई किया साइरोस ईवी को लॉन्च कर सकती है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा पंच ईवी के उच्च वेरिएंट्स से होने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले, किया साइरोस ईवी को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसका डिजाइन मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलता-जुलता रहेगा, लेकिन इसमें ईवी मॉडल के लिए कुछ विशिष्ट बदलाव भी किए जाएंगे। नई किया साइरोस ईवी में चार्जिंग पोर्ट को आगे बाईं तरफ व्हील आर्च के ऊपर लगाया गया है, जबकि आगे और पीछे के बंपर का डिजाइन नया होगा। कंपनी इसमें बेहतर एयरोडायनामिक्स वाले नए अलॉय व्हील्स भी दे सकती है। परीक्षण मॉडल में हरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स भी नजर आए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। वर्टिकल एलईडी हेडलैंप, एल आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट और वर्टिकल एलईडी टेललैंप जैसे फीचर्स पहले की तरह बरकरार रहने की संभावना है। इसमें 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) से जुड़े सेंसर भी दिए जा सकते हैं। केबिन के अंदर, नई किया साइरोस ईवी काफी हद तक पेट्रोल और डीजल मॉडल जैसी ही रहने की उम्मीद है। इसमें दो 12.3 इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने की संभावना है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे बैटरी को आदर्श परिस्थितियों में लगभग 30 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकेगा।

किआ इंडिया सिरोस ईवी को कर सकती है भारत में लॉन्च

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

भारतीय बाजार में किआ इंडिया अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है, और जल्द ही सिरोस ईवी को लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह किआ की भारत में सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो कैरेंस क्लैविस ईवी से नीचे रखी जाएगी।

इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, मारुति ई-विटारा और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसे मॉडलों से होगा। किआ सिरोस ईवी को 42 किलोवॉट-घंटा और 51.4 किलोवॉट-घंटा बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है। यह बैटरी क्षमता हुंडई क्रेटा ईवी और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के समान है, लेकिन सिरोस के छोटी और हल्की होने के कारण इससे बेहतर ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। 42 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ लगभग 443 किलोमीटर और 51.4 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ लगभग 520 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जा सकता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बना देगा।

सबसे खास बात यह है कि कंपनी इस गाड़ी के साथ इंडस्ट्री की सबसे अच्छी 15 साल या लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे सकती है, जो भारत में उपलब्ध सबसे व्यापक बैटरी कवरेज प्लान में से एक होगा। इसके साथ 3 साल की स्टैंडर्ड गाड़ी वारंटी भी मिलेगी, जिसे 7 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा। सिरोस ईवी का एक्सटीरियर इसके आईसीई (इंटरनल कंब्यूशन इंजन) वर्जन से काफी मिलता-जुलता होगा, जिसमें बॉक्सी आकार और ऊँचा स्टांस होगा, साथ ही ईवी-स्पेसिफिक फीचर्स जैसे व्हीकल-टू-लोड क्षमताएं भी मिल सकती हैं।

सेक्टर-16 में कैमरे की निगरानी में हो रही स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई

» फरीदाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई

मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने सेक्टर-16 में स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई का काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। इस अभियान की खास बात यह है कि पूरी सफाई प्रक्रिया की कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइन के भीतर कहीं भी सिल्ट या अन्य अवरोध शेष न रह जाए। नगर निगम के अनुसार, सेक्टर-16 में करीब 11 किलोमीटर लंबी स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग डेढ़ किलोमीटर हिस्से में काम अभी बाकी है। इसे भी जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर लाइन और नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम में जिन इलाकों में जलभराव की संभावना अधिक रहती है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जा रहा है। सेक्टर-16 में पिछले कुछ समय से लगातार मशीनों और कर्मचारियों की मदद से सफाई की जा रही है। कार्यकारी अभियंता (ओल्ड जोन) संजीव कुमार ने बताया कि स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई के बाद कैमरे के माध्यम से पूरी पाइपलाइन की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक करीब 11 किलोमीटर लंबी स्टॉर्म वाटर लाइन से जमा सिल्ट और गंदगी को निकाल दिया गया है। वर्षों से जमा सिल्ट के कारण कई स्थानों पर बारिश का पानी तेजी से नहीं निकल पाता था, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद लाइन की जल निकासी की क्षमता बढ़ेगी और बारिश के दौरान पानी का प्रवाह पहले की तुलना में अधिक सुचारु रहेगा। निगम का कहना है कि शेष डेढ़ किलोमीटर हिस्से का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकसः नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर लाइन और नालों की सफाई तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। साथ ही सभी कार्यों की नियमित निगरानी कर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्टॉर्म वाटर लाइन, नालों और ड्रेन में कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक, मलबा या अन्य अपशिष्ट सामग्री न डालें। अधिकारियों का कहना है कि सफाई के बावजूद यदि नालों और लाइनों में दोबारा कचरा डाला जाएगा तो जल निकासी प्रभावित होगी और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या फिर से पैदा हो सकती है।

दिल्ली में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत; चालक फरार

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई

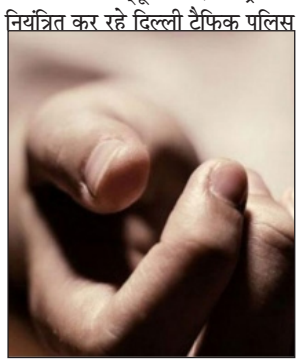

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार-कंझावला रोड पर गुरुवार को सड़क हादसे में तेज गति से आ रहे लोडेड डंपर ने एक महिला को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक घटना वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही अमन विहार थाना पुलिस और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, शव की शिनाख्त प्रियंका के रूप में हुई, जो दिल्ली के रोहिणी इलाके की रहने वाली थीं। शव को सड़क से हटाने के बाद पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया। अमन विहार पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह दर्दनाक हादसा ऐसे समय हुआ है, जब एक दिन पहले ही सिंघु बॉर्डर के पास ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी।

पिछले सप्ताह भी दिल्ली में एक हिट एंड रन मामले ने लोगों को झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस ने मर्सिडीज कार के चालक को गिरफ्तार किया था, जिसने 5 जुलाई को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास आउटर रिंग रोड पर एक स्कूटी सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया था। यह हादसा जीटीके बाईपास पर आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग पर फुटओवर ब्रिज के पास हुआ था।

संक्षिप्त खबरें

सीकरी और पियाला गांव में दो अवैध औद्योगिक कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

फरीदाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई। जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। डीटीपी ने बुधवार को गांव सीकरी और पियाला के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रहीं दो अवैध औद्योगिक कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 38 एकड़ भूमि पर बने अवैध निमार्णों को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार यजन चौधरी ने बताया कि गांव सीकरी में करीब आठ एकड़ और गांव पियाला में करीब 30 एकड़ क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रहीं औद्योगिक कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बुलडोजर से निमार्णाधीन 10 ढांचों, 22 चहारदीवारी और 18 डीपीसी को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। यजन चौधरी ने बताया कि बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध निमार्णों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड या औद्योगिक परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और संबंधित विभागों से स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

दुकान के गल्ले से चोरों ने उड़ाए 1.19 लाख रुपये

लोनी, यूटर्न/ 16 जुलाई। कोतवाली क्षेत्र के चिरोड़ी गांव स्थित मोबाइल की दुकान में घुसकर चोरों ने करीब 1.19 लाख रुपये गल्ले से निकाल लिए। घटना के दौरान दुकानदार शौचालय गया था। लोनी थाना पुलिस से चोरी की शिकायत की गई है। सिरोली गांव निवासी विशाल की चिरोड़ी गांव में मोबाइल फोन की दुकान है। पुलिस को दी शिकायत में विशाल ने बताया कि एक जुलाई की दोपहर में वह दुकान के पास शौचालय में गए और लौटते समय देखा कि दो युवक दुकान से बाहर आ रहे थे। दोनों युवक बाइक पर जल्दी में भाग गए। दुकान पर जाकर देखा तो गल्ला खुला हुआ था और उससे 1.19 लाख रुपये चोरी हो गए।

शिव नगर में जमीन खाली करने के नोटिस का विरोध, लोगों का प्रदर्शन

» फरीदाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई

बुलडोजर हमारी लाशों के ऊपर से गुजरेंगे....यह कहना है सेक्टर-22 स्थित शिव नगर की रहने वाली ज्योति कुमारी का। बुधवार को स्थानीय लोगों ने सीपीडब्ल्यूडी की जमीन खाली करने के नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया।

महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए।

प्रदर्शन के दौरान ज्योति कुमारी ने बताया कि उसका जन्म इसी बस्ती में हुआ था और अब उसकी उम्र 40 वर्ष है। उसके परिवार के राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली और पानी के कनेक्शन सहित सभी सरकारी दस्तावेज इसी पते पर बने हुए हैं। सरकार वर्षों से उनसे बिजली-पानी के बिल वसूलती रही, लेकिन अब अचानक इस बस्ती को अवैध बताकर हटाने की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय निवासी बबन गुप्ता ने बताया कि उसका परिवार करीब 50 साल से यहां रह रहा है। इतने वर्षों में कभी किसी विभाग ने आपत्ति नहीं जताई। अब अचानक जमीन को सरकारी बताते हुए मकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि जमीन खाली कराना चाहती है तो पहले रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराए।

लोग स्वयं कब्जा नहीं हटाते हैं तो 26 जुलाई से तोड़फोड़ अभियान : अभियंता

सीपीडब्ल्यूडी के अभियंता सुरेश कुमार के अनुसार, मुजेसर, सारन और सेक्टर-22 में स्थित पूर्व सरकारी प्रेस की करीब छह एकड़ जमीन 25 वर्ष पहले प्रेस बंद होने के बाद विभाग को हस्तांतरित हुई थी। लंबे समय तक भूमि का उपयोग नहीं होने के कारण उस पर लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए। विभाग का कहना है कि पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और मामला अदालत तक पहुंचा था। न्यायालय के आदेश के बाद अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम त्रिलोकचंद ने बताया कि नियमानुसार सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यदि निर्धारित समय तक लोग स्वयं कब्जा नहीं हटाते हैं तो 26 जुलाई से प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा।

आनंद पर्वत का 'बैड कैरेक्टर' चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी की बाइक और स्कूटर बरामद

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 जुलाई

दिल्ली में आनंद पर्वत थाना पुलिस ने वजहें चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आनंद पर्वत निवासी 36 वर्षीय सुभाष सिंह उर्फ 'मेंटल' के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की दो गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपी आनंद पर्वत थाने का घोषित 'बैड कैरेक्टर' है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई को आनंद पर्वत थाने में तैनात हेड कांस्टेबल रोहित को सूचना मिली कि नेहरू नगर स्थित रामलीला मैदान के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि नियमित गश्त पर तैनात कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल ओम प्रकाश ने पहले ही संदिग्ध व्यक्ति को रोक लिया था। पुलिस को देखते ही आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा, लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान जब मोटरसाइकिल की जांच की गई तो पता चला कि वह सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी और इस संबंध में पहले से मामला दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से लगातार पूछताछ की। इस दौरान उसने सराय रोहिल्ला इलाके से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। उसने यह भी बताया कि उसने एक और चोरी का स्कूटर रामलीला मैदान के पीछे स्थित मंदिर के पास छिपाकर रखा है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वहां से एक सफेद होंडा एक्टिवा स्कूटर बरामद किया। जांच में यह स्कूटर भी मोती नगर थाना क्षेत्र से चोरी किया गया निकला। पुलिस का कहना है कि दोनों वाहनों की बरामदगी के साथ मोटर वाहन चोरी के दो मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा हो गया है।

दूध के रुपये देने पर विवाद, जमकर मारपीट

खोड़ा, यूटर्न/ 16 जुलाई। थानाक्षेत्र में दूध के रुपये देने को लेकर दो पक्षों में मंगलवार देर रात जमकर विवाद हुआ। दुकानदार की तरफ से बुलाए गए हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामे के साथ-साथ मारपीट भी की। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची तो उनमें समझौता हो गया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मंगलवार देर रात खोड़ा स्थित दुकान पर एक व्यक्ति दूध खरीदने पहुंचा था। वहां दुकानदार के बेटे और खरीददार के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया। दुकानदार के बेटे ने अपने परिचित हिंदू संगठन के लोगों को मौके पर बुलाया तो उन्होंने हंगामा करते हुए मारपीट की। एसीपी ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया तो उनमें समझौता हो गया। इस दौरान थाने पहुंचने पर हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस के दुर्व्यवहार की बात भी कही हालांकि आरोप निराधार निकले। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

सोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाला

लोनी, यूटर्न/ 16 जुलाई। विपिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के लिए बॉर्डर थाना पुलिस की कई टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस का दावा है कि उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही सोनू को गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं, हत्यारोपी की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिवार में रोष है। बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार के यहां समाज के लोगों ने बैठक कर इस मामले पर चर्चा की।

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि विपिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू निवासी रतिराम कॉलोनी दिल्ली में छुपा हुआ है। बार-बार वह फोन खोल कर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी कई टीमें दिल्ली में ही है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसीपी ने यह भी कहा कि जल्द गिरफ्तारी न होने पर सोनू पर इनाम राशि बढ़ाई जाएगी। इधर, मृतक विपिन के परिवार को पुलिस ने सुरक्षा दी हुई है। वहीं, विपिन के भाई पवन ने बताया कि सोनू और उसके साथियों ने हत्या को अंजाम देने के बाद अब वह सोशल मीडिया से उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। घटना के बाद उसने कुछ लोगों को कॉल कर कर परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

अभिनेता अरबाज खान से तलाक के बाद मलाइका ने दूसरी शादी नहीं रचाई है, हालांकि उनकी डेटिंग की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन सबके बावजूद, मलाइका अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को पूरी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ संभालती हैं।

मलाइका अरोड़ा का बोल्ड अवतार देख फैंस हुए मदहोश

हाल ही में बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा ने ग्रीस वेकेशन से अपना एक शानदार वीडियो साझा किया है, जिसमें उनका बेहद बोल्ड और मनमोहक अवतार देख फैंस मदहोश हो गए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां मलाइका को अपने हर पल को खुलकर एन्जॉय करते देख उनके प्रशंसक भी खुशी से गदगद हो उठे हैं। वीडियो में मलाइका एक मजेंटा प्रिंटेड बैकलेस मोनोकनी पहने पूल में चिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से अपने टोंड फिगर को फ्लॉन्ट किया, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। खुले बाल और सटल मेकअप में मलाइका किसी डीवा से कम नहीं लग रही थीं, और उनकी मनमोहक अदाओं से नजरें हटाना दर्शकों के लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पूल में खूब मस्ती की, जिससे उनकी जीवंत और ऊजार्वान शख्सियत खुलकर सामने आई। इस वीडियो में मलाइका ने अपने आसपास के बेहद खूबसूरत नजारे को भी दिखाया झ नीले समंदर और आसमान के बीच उनका टशन और स्वैग किसी को भी अपनी ओर क्रेजी कर सकता है। मलाइका के इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। हजारों प्रशंसकों ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ की है। लोग उनकी बेमिसाल खूबसूरती, फिटनेस और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए नहीं थक रहे। उनकी इस उम्र में भी बरकरार यूथफुलनेस और बोल्डनेस कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।

मलाइका अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी रही हैं, जो उन्हें कई महिलाओं के लिए एक आदर्श बनाती है। अपने बोल्ड फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के साथ-साथ मलाइका अपनी लव लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं।

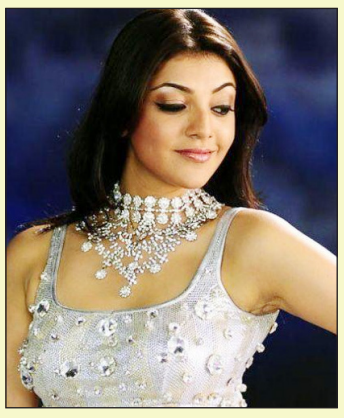

कोर्टरूम ड्रामा का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही थीं काजल अग्रवाल

अपनी आगामी फिल्म द इंडिया स्टोरी के साथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल पूरी तरह तैयार हैं। इसे लेकर काजल अग्रवाल ने अपनी उत्सुकता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से एक कोर्टरूम ड्रामा का हिस्सा बनने का इंतजार कर रही थीं। फिल्म द इंडिया स्टोरी ने आखिरकार उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में काजल अग्रवाल ने वकील अर्चना का सशक्त किरदार निभाया है। अर्चना एक ऐसी जुझारू वकील हैं जो समाज के आम नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। उनका संघर्ष उन शक्तिशाली कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ है जिन पर लोगों की जान खतरे में डालने और मुनाफा कमाने का आरोप है। यह फिल्म एक गहन कोर्टरूम ड्रामा और एक इन्वेस्टिगेटिव कहानी के माध्यम से कई गंभीर सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है, जिनमें फूड सेफ्टी, कॉर्पोरेट जवाबदेही और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां प्रमुख हैं। फिल्म का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण विषयों पर जनमानस में चर्चा शुरू करना है और समाज को जागरूक करना है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान बात करते हुए काजल अग्रवाल ने द इंडिया स्टोरी से अपने जुड़ाव और अपने किरदार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से मेरी पहली पसंद रहा है।

बेल्जियम के अनुभवी मिडफील्डर टिलेमैन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते नजर आयेंगे

» लंदन, यूटर्न/ 16 जुलाई ।

बेल्जियम के अनुभवी मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स अब इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के एक प्रमुख क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर खेलते हुए दिखेंगे। मैनचेस्टर ने मिडफील्डर यूरी के साथ जून 2031 तक के लिए करार किया है। यह ट्रांसफर सभी जरूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। वह 2026/27 सीजन से पहले माइकल कैरिक की टीम से जुड़ेंगे और नंबर 18 की जर्सी पहनेंगे। ये जर्सी क्लब के महान मिडफील्डर पॉल स्कोल्स ने 1996/97 सीजन से लेकर 2010/11 तक पहनी थी।

टिलेमैन्स ने बेल्जियम की ओर से 90 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और हाल ही में फीफा विश्व कप में बेल्जियम के क्वार्टर फाइनल तक के सफर में इनकी अहम भूमिका रही है। वहीं स्कोल्स जैसे दिग्गज की नंबर 18 की जर्सी पहनना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

क्लब से जुड़ने के बाद इस मिडफील्डन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी बड़ी टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, शब्दों में अपनी खुशी नहीं बतायी जा सकती है। इतने बड़े और ऐतिहासिक क्लब के लिए खेलना मेरे बचपन के सपनों में शामिल था। यह मेरी कई साल की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें अपने करियर में कई सफलताएं मिली हैं, लेकिन अब वे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में बड़ी ट्रॉफियां जीतनी हैं, और वे इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले सीजन में, टिलेमैन्स ने एस्टन विला के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने एससी फ्रीबर्ग के खिलाफ यूरोपा लीग फाइनल में गोल कर अपनी टीम को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिडफील्ड और अटैक दोनों भूमिकाओं में खेलने वाले टिलेमैन्स अपनी सटीक पासिंग और खेल को आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

स्टोक्स अब कलब क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे

» लंदन, यूटर्न/ 16 जुलाई ।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा है कि वह क्लब क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऐसे में अब स्टोक्स का अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलना तय है। स्टोक्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद वह आराम का अनुभव कर रहे हैं। स्टोक्स ने कहा कि व सफेद-गेंद प्रारूप में फ्रैंचाइजी की ओर से खेलने पर भी विचार करेंगे। उन्होंने डरहम के हेड कोच रयान कैंपबेल को एक संदेश भी भेजा जिससे साफ है कि वह अभी भी खेल को लेकर उत्साहित हैं। स्टोक्स ने कहा, इस सप्ताह कुछ पल ऐसे भी आए जो सच में बहुत कठिन थे और इन सब चीजों ने यह साफ कर दिया कि मैंने सही फैसला लिया है।

वहीं डरहम के हेड कोच कैंपबेल को पूरी उम्मीद है कि स्टोक्स इस गर्मी में वन-डे कप में खेलते दिखेंगे। यह टूर्नामेंट 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें डरहम का मुकाबला पहले राउंड में डबीर्शायर से होगा।

स्टोक्स का द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेलने के लिए कोई अनुबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस सत्र की नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। द हंड्रेड टूर्नामेंट भी उसी दिन शुरू हो रहा है, इसलिए जो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के लिए चुने गए हैं, वे अपनी काउंटी टीमों के लिए वन-डे कप में नहीं खेल पाएंगे, जब तक कि उनकी फ्रेंचाइजी उन्हें खेलने की अनुमति न दे दे। स्टोक्स के इस फैसले से इंग्लैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनके प्रशंसकों को क्लब स्तर पर अब उन्हें खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा।

एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए एक और तेज गेंदबाज शामिल करे इंग्लैंड : ब्रॉड

» बर्मिंघम, यूटर्न/ 16 जुलाई ।

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि अगामी एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए टीम में एक और तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया जाये। ब्रॉड के अनुसार इसका लाभ ये होगा कि एक तेज गेंदबाज बैकअप के तौर पर टीम के पास तैयार रहेगा। ब्रॉड के अनुसार भारत के खिलाफ पहले एकदिवसीय में मिली हार से टीम की कमजोरियां सामने आ गयी हैं। उन्होंने आगाह किया है कि यदि इन कमियों को अभी ठीक नहीं किया गया तो विश्वकप में टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रॉड का मानना है कि मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण के पास अभी दबाव बनाकर लगातर विकेट लेने के लिए पर्याप्त गेंदबाज नहीं हैं। जब भी अच्छी बल्लेबाजी वाली टीम सामने आती है। गेंदबाजी दबाव में आ जाती है। ब्रॉड के अनुसार भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबले में मेजबान टीम की गेंदबाजी कमजोर नजर आयी। उनके पास भारतीय बल्लेबाजों को रोकने या विकेट लेने के लिए असरदार गेंदबाज नहीं थे। इससे सफेद गेंद क्रिकेट में टीम की कमजोर सामने आ गयी। ब्रॉड के अनुसार एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने से टीम को न केवल अधिक विकल्प मिलेंगे बल्कि अलग-अलग हालातों और पिचों पर बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यह गेंदबाजों के वर्कलोड को भी साझा करेगा और उन्हें पूरे टूर्नामेंट में ताजा रखने में मदद करेगा। उनका मानना है कि अब से विश्व कप तक का समय नई रणनीतियों को आजमाने और युवा तेज गेंदबाजों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव देने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे बड़े मंच के लिए तैयार हो सकें। उनके अनुसार इंग्लैंड का एकदिवसीय रैंकिंग में आठवें स्थान पर खिसकना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ गंभीर सुधारों की आवश्यकता है।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

संक्षिप्त खबरें

होर्मुज से खार्ग तक जंग, अमेरिका ने की ईरान की नाकेबंदी

वॉशिंगटन, 16 जुलाई । अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है, जिसे पहले अप्रैल से जून के बीच भी लागू किया गया था। इस कदम का उद्देश्य ईरान पर दबाव बढ़ाना है। इसके साथ ही, अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में पहले से लागू सीजफायर पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। इन हमलों के जवाब में क्षेत्र के कई हिस्सों में धमाकों और पलटवार की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका के सहयोगी कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित खतरों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

यूक्रेन में बनेंगी फ्रांस की क्रूज मिसाइल

कीव, यूटर्न/ 16 जुलाई । फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की कि यूक्रेन को उसकी अपनी जमीन पर मिसाइल और बम बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पेरिस में आयोजित 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस फैसले से यूक्रेन की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और हथियारों का निर्माण तेजी से हो सकेगा। नए लाइसेंसिंग समझौतों के तहत यूक्रेन एस्टर-30 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, एएएसएम ग्लाइड बम और स्कैल्प -ईजी क्रूज मिसाइल का स्थानीय स्तर पर निर्माण करेगा।

6.51 लाख बच्चों को नहीं मिली एक भी खुराक

पाकिस्तान गंभीर महामारी के मुहाने पर खड़ा

» **कराची, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

पाकिस्तान के स्वास्थ्य महकमे की हालत कितनी नाजुक है, इसकी मिसाल जब-तब मिलती ही रहती है। फिलहाल जीरो-डोज वाले बच्चों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन (पीएमए) ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान एक गंभीर महामारी संबंधी संकट के मुहाने पर खड़ा है।

पीएमए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाकिस्तान में बड़ी संख्या में 'जीरो-डोज' बच्चों की मौजूदगी को लेकर तत्काल राष्ट्रीय रेड अलर्ट जारी किया है।

जीरो-डोज बच्चे वे बच्चे होते हैं, जिन्हें डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से बचाव वाली वैक्सीन (डीटीपी1) की पहली खुराक भी नहीं मिली होती है।

नियमित टीकाकरण व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रह गए 6.51 लाख शिशुओं के साथ, चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधि संगठन ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक गंभीर महामारी संबंधी संकट के मुहाने पर खड़ा है, जिससे बच्चों में रोकी जा सकने वाली बीमारियों और मौतों का बड़े पैमाने पर दोबारा प्रसार हो सकता है। पीएमए ने इसे औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करते हुए कहा कि टीकाकरण में इतनी बड़ी कमी से सामूहिक प्रतिरक्षा (हर्ड इम्युनिटी) बनाए रखने की सीमा प्रभावित हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में अनियंत्रित संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। प्रमुख दैनिक डॉन ने पीएमए के महासचिव डॉ. अब्दुल गफूर शोरों के हवाले से बताया, 'चिकित्सकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिये से देखें तो 5 लाख से अधिक जीरो-डोज बच्चों की मौजूदगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की गंभीर विफलता को दशार्ती है।'

उन्होंने कहा, 'इन भयावह आंकड़ों के पीछे एक गहरी और व्यवस्थित समस्या है, जिसने देश के स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर कर दिया है।' डब्ल्यूएचओ के नवीनतम क्षेत्रीय महामारी संबंधी आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र के कुल जीरो-डोज बच्चों में से 90 प्रतिशत के वल पांच देशों, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सोमालिया में हैं। जहां सूडान, यमन और सोमालिया सक्रिय युद्ध, अत्यधिक हिंसा या पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के पतन से जूझ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का इस सूची में शामिल होना मुख्य रूप से प्रशासनिक लापरवाही और शासन व्यवस्था की विफलता के कारण बताया गया है। शोरों ने कहा, 'किसी गैर-संघर्ष वाले देश में क्षेत्र के कुल जीरो-डोज बच्चों में से 14 प्रतिशत का होना शासन व्यवस्था की ऐसी विफलता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

इमरान खान की रिहाई को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ

» **इस्लामाबाद, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की संसदीय समिति ने पार्टी प्रमुख और पूर्व वजीर-ए-आजम इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी दिन इमरान खान की जेल में बंदी के तीन साल पूरे होंगे।

यह फैसला खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अंतरिम अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी के नेताओं ने संसदीय मामलों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन से बातचीत में कहा कि पार्टी के सांसदों ने आंदोलन शुरू करने के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है। इस आंदोलन में जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन और लंबा मार्च शामिल होंगे।

टकराव और मदद में कटौती से 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिल रही मदद

जेनेवा, यूटर्न/ 16 जुलाई । युद्ध का बोझ बहुत भारी होता है और महिलाओं को अक्सर इसकी कहीं अधिक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वीमन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय से जारी टकराव और मदद में कटौती के कारण जनवरी 2025 से 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संकट और संघर्ष से जूझ रहे 52 देशों में महिलाओं के नेतृत्व वाले और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले 855 संगठनों से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल 84 फीसदी संगठनों ने बताया कि उनकी सेवाओं की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन 10 में नौ संगठन मौजूदा आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण में शामिल पांच में से दो संगठनों को उम्मीद है कि वे अगले साल तक कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रकम की कमी की मुख्य वजह आधिकारिक विकास सहायता में आई भारी कमी है। यह विकास सहायता समिति (डीएसी) के 33 सदस्य देशों द्वारा दी जाने वाली सरकारी मदद का एक रूप है।

इटली का चुनावी संशोधन प्रस्ताव संसद में एक वोट से गिरा

रोम, यूटर्न/ 16 जुलाई । इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को संसद के निचले सदन में उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब चुनावी सुधार से जुड़े एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव को महज एक वोट से खारिज कर दिया गया। इस परिणाम ने न केवल सरकार की संसदीय ताकत पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर संभावित मतभेदों की भी चर्चा तेज कर दी है। जानकारी अनुसार बुधवार शाम गुप्त मतदान के जरिए हुए मतदान में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली (एफडीआई) द्वारा पेश किए गए संशोधन के पक्ष में 187 वोट, जबकि विरोध में 188 वोट पड़े। मतदान गुप्त होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने भी पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट दिया। खारिज किए गए संशोधन का उद्देश्य मतदाताओं को पार्टी सूची में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अधिकार देना था। सरकार का तर्क था कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे चुनावी व्यवस्था में अनावश्यक बदलाव बताया।

हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट देखने से बिगडी दर्शकों की तबीयत

» **लॉस एंजेलस, यूटर्न/ 16 जुलाई ।**

हॉरर फिल्म 'द एक्सॉर्सिस्ट' जिसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म को लेकर सालों से कई चौंकाने वाले दावे किए जाते रहे हैं। 'द एक्सॉर्सिस्ट' 53 साल पहले यानी 1973 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इसे देखने के दौरान कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। कुछ लोग बेहोश हो गए, तो कुछ के बारे में दावा किया गया कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थीं। यही वजह है कि आज भी यह फिल्म चर्चा का विषय बनी रहती है। यह एक हॉरर और मिस्ट्री फिल्म है, जिसकी कहानी एक छोटी बच्ची और उसके शरीर में कथित तौर पर प्रवेश कर चुकी बुरी आत्मा के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी, डरावने दृश्य और साउंड इफेक्ट्स उस समय दर्शकों के लिए बिल्कुल नए थे। रिलीज के बाद लोगों में इसे देखने की जबरदस्त उत्सुकता थी। करीब 104.96 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 3,858.94 करोड़ रुपये की कमाई कर इतिहास रच दिया। फिल्म की कहानी एक मासूम बच्ची के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर एक बुरी आत्मा का साया हो जाता है। इसके बाद बच्ची का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसकी मां, जो एक मशहूर अभिनेत्री होती है, बेटी की अजीब हरकतों से परेशान होकर उसे कई डॉक्टरों को दिखाती है। जब कोई इलाज काम नहीं आता, तो आखिर में वह एक पादरी की मदद लेती है, जो बच्ची से बुरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस फिल्म का हर सीन इतना खौफनाक है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। इस फिल्म को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स और चचाओं में दावा किया गया कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कई दर्शकों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।

हाई-स्पीड रेल ने 5.3 सेकंड में हासिल की 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

बीजिंग, यूटर्न/ 16 जुलाई । दुनिया भर में हाई-स्पीड रेल तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ भारत अपने रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाते हुए सेमी हाई-स्पीड और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को तेजी से गति दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने मैग्लेव तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने चुंबकीय तकनीक से संचालित एक हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन मॉडल को महज 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार तक पहुंचाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। यह गति भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की संभावित रफ्तार से करीब तीन गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के हुबेई प्रांत स्थित ईस्ट लेक लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने 1110 किलोग्राम वजनी हाई-स्पीड रेल मॉडल का यह सफल परीक्षण किया है।

भारत समेत 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाएगा अमेरिका

रुस से तेल खरीदने वालों के खिलाफ संसद में बिल पेश

» **वॉशिंगटन, यूटर्न/ 16 जुलाई**

अमेरिका के सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ एक नया प्रतिबंध बिल पेश किया है, जिसमें भारत पर भी 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। यह बिल 5 प्रमुख देशों झ भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान के निर्यात पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली आय पर लगाम कसना और उस पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नई भू-राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका बढ़ गई है।

यह नया बिल अप्रैल 2025 में सीनेट में लाए गए सेंक्शनिंग रशिया एक्ट का एक नरम संस्करण है। पुराने बिल में 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिस पर अमेरिकी संसद में सहमति नहीं बन पाई थी।

नए बिल में इस अधिकतम टैरिफ की सीमा को घटाकर 100 प्रतिशत तक सीमित किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी काफी गंभीर हो सकता है। नए बिल के तहत खास तौर पर चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान को लक्षित किया गया है, जो वर्तमान में रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं।

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, C/O Ummpl Marketing Pvt. 194-G, Sector 63, Noida 201307, Editor: Sandeep Sharma
Contact - +91 9888200619

* तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आर.बी.एक्ट. के तहत जिम्मेवार *